

Dixon

An ISO 9001 : 2008, 14001 : 2004 Company

Dixon Technologies (India) Ltd.

(Formerly Known as Dixon Technologies (India) Pvt. Ltd)

CIN : L32101UP1993PLC066581

Regd. Office : B-14 & 15, Phase-II, Noida-201305, (U.P.) India, Ph.: 0120-4737200

E-mail : info@dixoninfo.com. Website : http://www.dixoninfo.com, Fax : 0120-4737263

15-01-2021

To Secretary Listing Department BSE Limited Department of Corporate Services Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001	To Secretary Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Mumbai - 400 051
Scrip Code - 540699 ISIN: INE935N01012	Scrip Code- DIXON ISIN: INE935N01012

Dear Sir/Madam,

**Sub: Submission of copies of newspaper publication under Regulation 47(3) of the SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

In furtherance to our letter dated 14th January, 2021 and pursuant to Regulation 47(3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of Notice of the Board Meeting published in the following newspapers on 15th January, 2021:

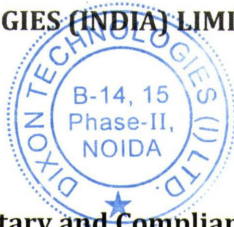
1. Business Standard- English
2. Business Standard- Hindi

We request you to kindly take this on your record.


Thanking You,

For DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LIMITED


Ashish Kumar
Group Company Secretary and Compliance Officer



Encl: as above



नोबल कॉ-आपरेटिव बैंक लि.

प्रधान कार्यालय: रघुनाथपुर, एम.पी.-1 रोड, सेक्टर-22, नोएडा
फोन: 0120-4503015, ई-मेल: ncbnoida@gmail.com

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

परिशिष्ट-IV-ए (नियम 8(6) का प्रावधान देखें नियम 9(1) भी पढ़ें)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित विस्तार आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा सर्व साधारण और विशेषकर कर्जदार(ओं) और जमानती(ओं) को सूचित किया जाता है कि प्रत्याभूत ऋणदाता को बंधक अधोलिखित अचल संपत्ति जिसका सांकेतिक कब्जा नोबल कॉ-आपरेटिव बैंक लि. (अचल प्रत्याभूत ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, नीचे वर्णित राशि की वसूली के लिए 'जो है जैसी है' और 'जैसी है जहाँ है' और 'जो भी है' आधार पर बिक्री की जायेगी। कर्जदार, जमानती, प्रत्याभूत परिसंपत्ति, देय राशि, आरक्षित मूल्य, ई-नीलामी तिथि व समय, ई-पंजीब और बोली वृद्धि राशि का विवरण निम्नवत् है:-

कर्जदार/जमानती का नाम और पता:
ऋण खाता: श्री सतपाल यादव (कर्जदार) पुत्र श्री जय चंद यादव, निवासी खसर नं. 34एम, गांव रसूलपुर नवादा, सेक्टर-62, नोएडा, श्री जयचंद यादव (जमानती) पुत्र स्व. श्री वेतराम यादव, निवासी खसर नं. 34एम, गांव रसूलपुर नवादा, सेक्टर-62, नोएडा

कुल बकाया: मांग सूचना तारीख और बकाया राशि:
ऋण खाता एलएपी 24 में दिनांक 18 सितंबर, 2018 को रु. 88,36,679/- (अठारही लाख छत्तीस हजार छह सौ उनहत्तर) + आगे की लागू साधारण ब्याज + पीनल ब्याज + विधिक प्रभार + वसूली प्रभार + विधिक प्रभार और अन्य व्यय उपरोक्त बकाया ऋण राशि में पूर्व में शामिल नहीं सीमा तक)
ऋण खाता बीएल 23 में दिनांक 7 मार्च, 2020 को रु. 4,94,873/- (चार लाख चौरानवे हजार आठ सौ तेसहत्तर) + आगे की लागू साधारण ब्याज + पीनल ब्याज + विधिक प्रभार + वसूली प्रभार + विधिक प्रभार और अन्य व्यय उपरोक्त बकाया ऋण राशि में पूर्व में शामिल नहीं सीमा तक)
ऋण खाता टीएल 175 में दिनांक 27 जुलाई, 2020 को रु. 33,93,599/- (तीस लाख तिरानवे हजार पाँच सौ नित्यानवे) + आगे की लागू साधारण ब्याज + पीनल ब्याज + विधिक प्रभार + वसूली प्रभार + विधिक प्रभार और अन्य व्यय उपरोक्त बकाया ऋण राशि में पूर्व में शामिल नहीं सीमा तक)

कब्जे की तिथि: सांकेतिक कब्जा
ईपंजीब और निविदा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि व समय: 30.01.2021 समय अप. 4:00 तक

क्र. सं.	ज्ञात ऋणधारों के साथ अचल संपत्ति का विवरण-	आरक्षित मूल्य, ईपंजीब, बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि व समय
1.	श्री सतपाल यादव पुत्र श्री जय चंद यादव के पक्ष में पंजीकृत आवासीय पूर्ण स्वामित्व संपत्ति स्थित खसर नं. 34एम, गांव रसूलपुर नवादा, सेक्टर-62, नोएडा, उत्तर प्रदेश, रापुर एरिया 422.23 वर्ग मीटर के समस्त भाग व खंड। परिष्क: साइट प्लान के अनुसार ऋणधार: उपर्युक्त के अलावा ज्ञात नहीं	आरक्षित मूल्य: रु. 2,10,00,000/- (दो करोड़ दस लाख) ईपंजीब: रु. 21,00,000/- (इकतीस लाख) बोली वृद्धि राशि: रु. 50,00,000/- (पचास हजार)	01.02.2021 को अप. 03.00 से अप. 04.00 तक (प्रत्येक 10 मिनट अवधि के असीमित विस्तारों के साथ)

- बिक्री के निबन्धन:**
- नीलामी बिक्री वेबसाइट <https://sarfaesi.auctiontiger.net> और हमारे ऑनलाइन टाइटल मोबाइल ऐप के माध्यम से दिनांक 01.02.2021 को अप. 03.00 से अप. 04.00 तक प्रत्येक 10 मिनट अवधि के असीमित विस्तारों के साथ ऑनलाइन ई-नीलामी/निविदाकरण होगी। प्रत्याभूत परिसंपत्ति आरक्षित मूल्य से कम बिक्री नहीं की जायेगी।
 - इच्छुक निविदाकारों के पास केब ई-मेल आईडी होनी चाहिए। विवरण के लिए कृपया मैसर्स ई-प्रक्रोयमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अहमदाबाद, संपर्क व्यक्ति: राम प्रसाद- 8000023297, निताश झा- 8800896847, ई-मेल आईडी: delhi@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net, लैंडलाइन- 079-61200559/595/596, निशुल्क नं: 18001035342 को संपर्क करें।
 - निविदाकार अपनी निविदाएं जमा करने और ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पूर्व विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए <https://sarfaesi.auctiontiger.net> और हमारे ऑनलाइन टाइटल मोबाइल ऐप देखें।
 - सम्बन्धी निविदाकारों ई-नीलामी पर मैसर्स ई-प्रक्रोयमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अहमदाबाद, संपर्क व्यक्ति: राम प्रसाद- 8000023297, निताश झा- 8800896847, ईमेल आईडी: delhi@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net, लैंडलाइन- 079-61200559/595/596 से ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
 - निविदाएं संबंधित विवरण के साथ निश्चित प्रारूप में केवल ऑनलाइन प्रक्रिया से जमा करने होंगी।
 - घरोर राशि जमा (ईपंजीब) राशि ऑनलाइन निविदा जमा करने से पूर्व खाता नं. 9999001004421, खाता नाम: सरकारी ई-नीलामी, नोबल कॉ-आपरेटिव बैंक लि., आईएफएससी कोड: YESBNCB001 में आरटीजीएस/एनईएफटी/निधि अंतरण के माध्यम से जमा की करनी होगी।
 - ऑनलाइन जमा किए गए निविदा फॉर्म की एक प्रति अनुत्तरनाकों (यूटीआर नं. भी लिखें) के साथ प्राधिकृत अधिकारी, नोबल कॉ-आपरेटिव बैंक लि., एच.ओ. रघुनाथपुर, एम.पी.-1 रोड, सेक्टर-22, नोएडा, जिला नोएडा नगर को अर्पित करें या साइट कॉपी ईमेल से recovery@nobלבank.in पर अर्पित करें। निविदा मूल्य आरक्षित मूल्य से अधिक होना चाहिए और निविदा रु. 50,000/- (रुपये पचास हजार) के गुणक में अपने प्रस्ताव बढ़ा सकते हैं। सफल निविदाकार के ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही समाप्त के 24 घंटों के अंदर ऊपर खंड-6 में बताए अनुसार प्रत्येक की 25% (पहले ही मुगुतान की गई घरोर राशि सहित) मुगुतान करनी होगी। निश्चित बोली राशि की 25% राशि की शेष राशि के मुगुतान में बूक पर ईपंजीब राशि जमा हो जानेगी और प्रत्याभूत परिसंपत्ति दूबारा बेची जायेगी। बोली राशि की शेष 75% राशि उनको बिक्री स्वीकृति/पुष्टि दिए जाने के 15 दिनों के अंदर ऊपर खंड-6 में बताए अनुसार ही मुगुतान करनी होगी। निश्चित अवधि के अंदर बोली राशि की शेष 75% राशि के मुगुतान में बूक पर जमा राशि जमा हो जानेगी और प्रत्याभूत परिसंपत्ति दूबारा बेची जायेगी।
 - असफल निविदाकारों की ईपंजीब राशि नीलामी की तिथि से 7 दिनों के अंदर वापस कर दी जायेगी और निविदाकार किसी ब्याज, लागत, व्यय या अन्य प्रभार (यदि कोई हो) का दावा करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।
 - बिक्री बैंक के अनुमोदन के तहत है। यदि कर्जदार/जमानती बैंक को देय राशि का बिक्री से पूर्व पूर्ण मुगुतान कर देता है तो बिक्री आयोजित नहीं होगी। बिक्री "जो है, जहाँ है" और "जहाँ है, जैसी है" शर्त पर बेची जायेगी और इच्छुक निविदाकार बैंक के प्रमाणों के अतिरिक्त संपत्ति पर किसी अन्य प्राधिकरण के किसी अन्य दावे, प्रभार के संबंध में अपनी जांच कर लें और अपनी निविदा जमा करने से पूर्व हक, सौभाग्य, और संपत्ति परिष्कार के बारे में स्वयं संतुष्ट हो लें। बिक्री की जा रही संपत्ति पर किसी प्रकार के कोई दावे, प्रभार/ऋणधार या अन्य किसी मामले आदि में ऑनलाइन निविदा जमा होने के बाद कोई विचार नहीं किया जायेगी।
 - अधोहस्ताक्षर को बिना कोई पूर्व सूचना दिये किसी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार अथवा बिक्री स्वामित्व/निस्तार करने अथवा बिक्री के निपट में एवं शर्तों में बदलाव करने का पूर्ण अधिकार और स्वतंत्रता होगी।
 - सफल खरीदार को सरकार को सभी लागू स्टाम्प शुल्क, प्रभार (बैंक द्वारा जारी बिक्री प्रमाणपत्र के शामिल), पंजीकरण प्रभार, सरकार को देय सभी सांविधिक बकाया, कर और दरे (उक्त संपत्ति के संबंध में वर्तमान और भविष्य में उत्पन्न होने वाले) स्वयं वहन करने होंगे। बिक्री प्रमाणपत्र केवल सफल निविदाकार के नाम में जारी किया जायेगा।
 - इच्छुक निविदाकार उपरोक्त उल्लिखित तिथि एवं समय पर अपने खर्चे पूर्व ऑनलाइन टैलर संपत्ति की जाँच-परख/निरीक्षण कर सकते हैं। संपत्तियों के निरीक्षण के लिए कृपया प्रधान कार्यालय में फोन नं. 0120-4503010, 0120-4503013 पर संपर्क करें।
 - अन्य किसी जानकारी के लिए प्राधिकृत अधिकारी, वसूली विभाग, नोबल कॉ-आपरेटिव बैंक लि., एच.ओ. रघुनाथपुर, एम.पी. रोड-1, सेक्टर-22, नोएडा से संपर्क किया जा सकता है।
- दिनांक: 15.01.2021**
- प्राधिकृत अधिकारी, नोबल कॉ-आपरेटिव बैंक लि.**

Sub Broker/ Authorised Person Name	Trade Name	Exchange Registration Numbers of Sub Broker/ Authorised Person	Address of Sub Broker/ Authorised Person
AMARDEEP SINGH BHATIA	AMARDEEP SINGH BHATIA	NSE - AP0291103241	13A/18, W.E.A., Karol Bagh, Delhi-110005
AMIT KUMAR	AMIT KUMAR	NSE - AP0291105141	Flat No 8 Plot No 19, Road No 41 Ground Floor, Punjabi Bagh West Delhi, New Delhi-110026
BHAVANA PANT	BHAVANA PANT	NSE - AP0291106321	F 141 5 A 4 1st Floor Gali No. 11 West Vinod Nagar Shakar, Pur Baramad East Delhi, Delhi-110092
DIVIT ARORA	DIVIT ARORA	BSE - AP0106730169366 NSE - AP0291092611	8 21 First Floor Patel Hospital West Patel Nagar Patel Nagar, New Delhi Central Delhi, Delhi-110008
GAURAV MITTAL	GAURAV MITTAL	BSE - AP0106730197587 NSE - AP029101561	A/1240 Safdarjung Enclave, Safdarjung Enclave, South, West Delhi, Safdarjung Enclave, Delhi-110029
GEETA SANGHI	GEETA SANGHI	NSE - AP0291107621	246 Nigiti Apartment, Opp St George School, Alaknanda Kalkaji South, Delhi-110019
JAVED GANI	JAVED GANI	NSE - AP0291098301	H No-622, Shakurpur, New Delhi North West, Delhi-110034
KARAN ARORA	KARAN ARORA	BSE - AP01067301106713 NSE - AP0291105181	House No 44 Second Floor Near, Rameshwar Nagar Gundurwa, Model Town III North West Delhi, Delhi-110009
KUNAL KUMAR GUPTA	KUNAL KUMAR GUPTA	BSE - AP01067301103293 NSE - AP0291103811	Flat No-5, 2nd Floor, H No-108-AB, Munirka Infront of, Canara Bank Atm Village Mumukshu J.N.U., Delhi-110067
LOTUS INTERNATIONAL	LOTUS INTERNATIONAL	NSE - AP0291105651	MplNo 758 759 1 Street F 1, Gali Me Htab Rai Kunde, Wajima Ajmeri Gate, Delhi-110006
MAMTA RANI	MAMTA RANI	NSE - AP0291108801	D 32 627 Ground Floor, Gali No 4 Ganesh, Nagar II Shakurpur, Delhi-110092
MANINDER PAL SINGH	MANINDER PAL SINGH	BSE - AP0106730111452 NSE - AP0291108461	H 15 Shoop No 4, Vijay Nagar, Delhi-110009
NARENDRA SINGH NEGI	NARENDRA SINGH NEGI	NSE - AP0291092971	E-64 Harswarup Colony Pathpur, Bari Fatih Pur Bari South Delhi/Delhi, Delhi-110074
NEHA SINGH	NEHA SINGH	NSE - AP0291107501	Flat No 178 E Pocket, 1 Mayur Vihar, Phase I East Delhi, Delhi-110091
PINKI AGARWAL	PINKI AGARWAL	BSE - AP0106730111203 NSE - AP029108221	F 16 12 3rd Floor, Krishna Nagar, East Delhi, Delhi-110051
PRAVESH SHARMA	PRAVESH SHARMA	NSE - AP0291105441 MCX - 129423	Viz 235 H Indrapuri, I A R I, Central Delhi, New Delhi-110012
SANDEEP KUMAR GUPTA	SANDEEP KUMAR GUPTA	NSE - AP0291105761	House No 154 Near Police Station, Sarai Rohilla Vivekanand Malka Ganj North Delhi, Delhi-110007
SAROJ KUMAR JHA	SAROJ KUMAR JHA	NSE - AP0291108371	S 26 Prem Nagar Kiritri, Suleman Sullianpuri C, Block North West Delhi, Delhi-110086
SHIV RATAN BHAUKA	SHIV RATAN BHAUKA	BSE - AP01067301109153 NSE - AP029106781	R No 9, F Flr, 2812 Nayya Bazar, Delhi-110006
VED PRAKASH	VED PRAKASH	BSE - AP0106730182204 NSE - AP0291099501	W 235 H Indrapuri, I A R I, Central Delhi, New Delhi-110012

Please note that above mention Sub Brokers (SB)/Authorised Person (AP) are no longer associated with us. Any person henceforth dealing with above mention SB/AP should do so, at their own risk. Kotak Securities Ltd. shall not be liable for any such dealing. In case of any queries for the transactions till date, Investors are requested to inform Kotak Securities Ltd. within 15 days from the date of this notification, failing which it shall be deemed that there exists no queries against the above mentioned SB/AP.

Kotak Securities Limited, Registered Office: 27 BKC, C 27, G Block, Kotak Securities, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400051. CIN: U99999MH1994PLC134051, Telephone No.: +22 43360000, Fax No.: +22 67132430. Website: www.kotak.com, www.kotaksecurities.com. Correspondence Address: Infinity IT Park, Bldg. No 21, Opp. Film City Road, A K Vaidya Marg, Malad (East), Mumbai 400097. Telephone No: 42856825, SEBI Registration No: INZ000200137 (Member of BSE, NSE, MSE, MCX & NCDCE), AMFI ARN 0164, PMS INP00000258, and Research Analyst INH000000586, NSDL/CDSL: IN-DP-NSDL-23-97.



श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: कार्यालय सं. 123, अंगणा नैकेन स्ट्रीट, चेन्नई-600 001
शाखा कार्यालय: प्लॉट सं. 16, कॉर्पोरेशन बैंक के ऊपर, टाउन हाल लिंक रोड, उदयपुर-313001, राजस्थान, वेबसाइट: <http://www.shriramcity.in>

आर्थिक कब्जा सूचना

जैसा कि अधोहस्ताक्षर ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (कथित अधिनियम) के प्रावधानों के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (कथित नियम) के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड (एससीएफएफ) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदारों को कथित मांग सूचनाओं में उल्लिखित राशि का पुनर्मुगुतान करने को कहते हुए मांग सूचनाएं निर्गत की थीं जिसका विवरण निम्नलिखित तालिका में है। राशि के पुनर्मुगुतान में कर्जदार के असफल होने के कारण एतद्वारा कर्जदारों तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षर ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में यहाँ नीचे वर्णित संपत्ति पर 12 जनवरी, 2021 को भौतिक कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदार को तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नीचे वर्णित राशि तथा उरस पर ब्याज के लिए श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार का नाम एवं पता	मांग सूचना	सम्पत्ति का विवरण
1. मैसर्स जय गणेश ब्रिक उद्योग (ग्रोप. अर्जुनलाल प्रजापत) डकन कोटरा, तहसील-गिरवा, उदयपुर (राज.)-313001	2 अप्रैल, 2019 तक रु. 95,99,975/- (रुपये पचासवे लाख नित्यानवे हजार नौ सौ पचहत्तर मात्र)	1. खसर नं. 2348, 2349 तथा 2355, ग्राम सरसिया काड, तहसील मंडल, पलोदरा, पहासील सरदा, उदयपुर पर स्थित औद्योगिक सम्पत्ति की भूमि का सम्पूर्ण भाग, माप 4300 वर्ग मीटर, उदयपुर में स्थित (प्रोपराइटर स्वामी अर्जुन लाल प्रजापत पुत्र गणेश लाल) सीमाएं: उत्तर: कृष्णा अर्जुन ब्रिक्स की भूमि, दक्षिण: नंजी पुत्र देवा की भूमि, पूर्व: सड़क, पश्चिम: नाला
2. श्री अर्जुनलाल प्रजापत अन्नामाता घाटी, तीतारपी, डकन कोटरा, गिरवा, उदयपुर, राजस्थान-313001		
3. श्रीमती प्रेमलता प्रजापत अन्नामाता घाटी, तीतारपी, डकन कोटरा, गिरवा, उदयपुर, राजस्थान-313001		

प्रतिभूति आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिपेक्ष्य में कर्जदारों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

स्थान: उदयपुर
थिथि: 15/01/2021

श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड



DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LIMITED

Registered Office: B-14 & 15, Phase-II, Noida, Gautam Buddha Nagar, UP-201305
E-Mail: investorrelations@dixoninfo.com
Website: www.dixoninfo.com
Phone: +91-120-4737200, Fax: 0120-4737263, CIN: L32101UP1993PLC066581

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 2nd February, 2021, to inter-alia, consider and approve the Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results (provisional) for the Period ended as on 31st December, 2020.

Further, in accordance to the Reg. 46 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the details of the aforesaid meeting are available on the website of the Company i.e. www.dixoninfo.com and the website of the Stock Exchanges where the Company's shares are listed viz. BSE Limited (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com)

For Dixon Technologies (India) Limited
Sd/-
Ashish Kumar
Place: Noida Group Company Secretarial
Date: 14.01.2021 Head & Legal & HR

कब्जा सूचना

जबकि, असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (आर्सिल) के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचनाएं जारी की थीं, जिनमें निम्नलिखित कर्जदारों से उक्त सूचनाओं में उम्मेद संबंधित नाम के सामने वर्णित राशियां, उज पर लागू दरों पर ब्याज के साथ, उक्त सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर, आगे मुगुतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार ब्याज, उपगत किए गए अनुबंधी खर्च, लागत, प्रभार इत्यादि चुकाने की मांग की गई थी।

क्र. सं.	कर्जदार का नाम/सह-कर्जदार का नाम/ऋण खाता संख्या	कुल बकाया राशि (रु. में)/पिगत तिथि	कब्जा की तिथि एवं प्रकार
1	सत्य नारायण मीणा / सुनीता मीणा/ 401डीएचएचएच36711397/ 401डीएचएचएच34411292	रु. 36,33,474.96/- 31-08-2020	सांकेतिक 12.01.2021

संपत्ति का वर्णन: कीरोल्ड डीडीए विल्ड-अप, एलआईडी प्लेट नंबर-18, चतुर्थ तल, ब्लॉक-ई, पार्क-1, सेक्टर-18 रोडिणी आवासीय योजना दिल्ली-110089, जिसका क्षेत्रफल (फ्लैट) 42 वर्ग मी. है।

जबकि इसमें ऊपर वर्णित कर्जदार बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्वारा कर्जदारों को विशेष रूप से और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि आर्सिल के अधोहस्ताक्षर ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उक्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहाँ ऊपर वर्णित संपत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों का **सांकेतिक कब्जा** उपरोक्त तिथियों को प्राप्त कर लिया है। विशेष रूप से ऊपर वर्णित कर्जदारों तथा जनसाधारण को उपरोक्त संपत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और उपरोक्त संपत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार आर्सिल के प्रभार के अधीन होगा।

स्थान: दिल्ली
थिथि: 15-01-2021

असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड



असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड

सौआईएन: U65999MH2002PLC134884, वेबसाइट: www.arcil.co.in

पंजीकृत कार्यालय: डेव ब्लॉक, 10वां तल, 29, सेनापति बाट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400028, फोन: +91 2266581300

शाखा पता: द्वितीय तल, सेटी वैम्बर्, प्लॉट नंबर 2, डीडीए लोकल शॉपिंग सेंटर, न्यू राजिवंदर नगर, नई दिल्ली-110060, फोन: 011-46370444



Punjab & Sind Bank

(A Govt. of India Undertaking)

जहाँ सेवा ही जीवन- ध्येय है

नेहरू ग्राउंड, आर्या समाज रोड, एनआईटी, फरीदाबाद फोन नं. 0129-25415773, ई-मेल: f0471@psb.co.in


[नियम 8(1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्तियों के लिए)

यह सूचना दी जाती है कि, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (200 का 54) और धारा 13(12) के सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, निम्न वर्णित तालिका में उल्लिखित दिनांक पर धारा 13(2) के अंतर्गत एक मांग सूचना जारी करते हुए सूचनाओं में उल्लिखित देय राशि को कथित सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर मुगुतान करने की मांग की गई है। जैसा कि कर्जदार (ओं) देय राशि का मुगुतान करने में विफल रहे हैं, कर्जदार (ओं) गारंटर (ओं) और आम जनता को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षर ने अधिनियम की धारा 13(4) के सह पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत उसे उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न वर्णित तालिका में संपत्ति पर कब्जा प्राप्त कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदार (ओं) गारंटर (ओं) और आम जनता को एतद्वारा सावधान किया जाता है कि वे कथित संपत्ति के साथ किसी प्रकार का लेनदेन न करें और उनके द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का लेनदेन **पंजाब एण्ड सिंध बैंक**, नेहरू ग्राउंड, आर्या समाज रोड, एनआईटी, फरीदाबाद (हरियाणा) शाखा को नीचे दी गई देय राशि पर उसके भविष्य के ब्याज, लागतों और अन्य व्यय इत्यादि सहित प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदारों/गारंटर्स/बंधकर्ताओं के नाम	अचल संपत्ति का विवरण	सूचना के अनुसार बकाया राशि	सूचना की दिनांक	कब्जे की दिनांक
मेसर्स वीलव डीजीनिअर्स (कर्जदार) (3) श्री दाल चंद पुत्र श्री राम धन शर्मा (गारंटर) (2) श्री दाल चंद शर्मा पुत्र श्री राम धन शर्मा और (4) श्रीमती ममता पत्नी श्री दाल चंद (गारंटर)	अचल संपत्ति का संपूर्ण और स्वामीण भाग, जिसमें खसर नं. 165/6/1/1(5-7) (जो अब मकान नं. 297 का शामिल है), नई कॉलोनी, इस्लामाबाद, पलवल, हरियाणा) माक क्षेत्र 4 मरिया (121) वर्ग गज श्री टेक चंद शर्मा पुत्र श्री राम धन शर्मा से संबंधित की पंजीकृत प्रमाण नं. 10405 दिनांक 05.02.2007 संपत्ति का सीमांकन: उत्तर-श्री लक्ष्मण की संपत्ति, पश्चिम-श्री कृष्ण चंद की संपत्ति, पूर्व-रास्ता, दक्षिण-खाती प्लाट	रु. 15,88,960.43 (रुपये पंद्रह लाख अठ्ठासी हजार नौ सौ सात और तैकतीस मात्र) दिनांक 31.07.2015 तक (31.07.2015 तक ब्याज सहित) संस दिनांक 01.08.2015 से भविष्य का ब्याज उपरोक्त राशि पर लागू दर पर और आकारिभिक और अन्य विधि व्यय लागत, प्रभार इत्यादि सहित।	06.08.2015	11.01.2021

दिनांक: 14.01.2021

स्थान: फरीदाबाद प्राधिकृत अधिकारी (पंजाब एण्ड सिंध बैंक)



Punjab & Sind Bank

(A Govt. of India Undertaking)

जहाँ सेवा ही जीवन- ध्येय है

शाखा- दिल्ली रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश फोन नं. 0121-2529597 ई-मेल: m0621@psb.co.in

'परिशिष्ट IV दिखें नियम 8(1) प्रतीकात्मक कब्जा सूचना सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत (अचल सम्पत्ति के लिए)

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधिन और उक्त अधिनियम तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 9 के साथ पठित नियमावली 2002 के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत सूचना बैंक में निर्गत दिनांक पर कर्जदारों और गारंटर्स को एक मांग सूचना जारी कर बकाया राशि को उक्त सूचना की दिनांक से 60 दिनों के भीतर मुगुतान करने की मांग की थी। कर्जदारों एवं गारंटर्स को सूचना में असफल रहे हैं, एतद्वारा कर्जदारों एवं गारंटर्स को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षर ने उक्त नियमावली 2002 की धारा 13(4) के साथ पठित नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहाँ निम्न तालिका में वर्णित दिनांक पर सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदारों और गारंटर्स को तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को इस सम्पत्ति के संबंध में कोई लेन-देन नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और सम्पत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार **पंजाब एण्ड सिंध बैंक**, शाखा दिल्ली रोड, मेरठ, उ.प्र. की बकाया राशि और उस पर देय ब्याज के प्राभारधीन होगा।

खाते का नाम/कर्जदार/गारंटर	अचल सम्पत्ति का विवरण	राशि (नियम 13(2) के अंतर्गत सूचना में दर्शायी)	सूचना की दिनांक	कब्जे की दिनांक
मेसर्स जे.डी.एम. टेक इंडिया कंस्ट्रक्शन एण्ड विल्डर्स श्री विश्व सहाय पुत्र वकील सहाय (गौरीशंकर और शंकरका) निवास अग्रवाल लाल खाल नं. 1774, आनंद कॉलोनी, कालंदी कॉलोनी के पास बाणपुर बड, मेरठ 250002 और श्री स्वर्णि कृष्ण पुत्र मोहनचंद्र शशीम सुंन (गारंटर), 313, कागुन गंगा, लाला का बाजार घंटा घर, मेरठ-250002	1. खसर नं. 1774, आनंद कॉलोनी, कालंदी कॉलोनी के पास, क्षेत्र क्षेत्र 2.74 वर्ग मीटर पूर्व की तरफ: 30 फुट, उसके बाद अंतर की संपत्ति का ब्याज आगे भाग, पश्चिम की तरफ: 30 फुट, उसके बाद 15 फुट चौड़ा रास्ता, उत्तर की तरफ: 8 फुट 2 इंच उसके बाद अन्य की संपत्ति, दक्षिण की तरफ: 89 फुट 2 इंच उसके बाद अन्य की संपत्ति	रु. 14,28,739.30/- दिनांक : 30.09.2020 तक ब्याज सहित और अन्य भविष्य के ब्याज, व्यय और अन्य प्रभारों इत्यादि सहित।	27.10.2020	11.01.2021

Rlys on the beaten track

The national transport utility's long-awaited draft national plan merely reiterates a direction that has already been set

TWESH MISHRA
New Delhi, 14 January

Four years after a National Rail Plan (NRP), a vision document setting out the long-term investment for the Indian Railways, was first proposed, a draft was floated for public comment in December last year. But its content is unlikely to surprise those who track this sector. If anything, it continues along the tracks already set. Increasing the speed of trains and more private participation is definitely on the agenda, as is the proposal for weaning the Indian Railways from diesel to environmentally friendly electric locomotives.

"A central feature of the draft National Rail Plan is the emphasis on electrification of railway network and the dedicated freight corridors (DFCs). These corridors will allow faster speeds for goods trains that were otherwise not given preference over passenger trains such as the Shatabdi and Rajdhani on popular routes. The DFCs will also free up the train networks for more efficient plying of passenger trains," said Satish Mohan Singla, former member, Railway Board, adding, "These concepts are not new and they have been in the works for a long time now."

This much awaited National Rail Plan was initially spelled out by then Railway Minister Suresh Prabhu in the February 2016 Railway Budget speech. That also happened to be the last Railway Budget speech to be separately delivered and it was said that the National Rail Plan-2030 would be revealed a year from then.

Later in December 2016, Prabhu launched a dedicated website to collect stakeholders' inputs on this plan. The vision then was for integrated planning and cost optimisation by laying the new railway lines and new highways together in tunnels and over mega-bridges. That grand plan appears to have been repurposed in the proposed draft National Rail Plan for India which now takes the year 2050 as the horizon. But the document falls back to 2030 for developing capacity that will cater to growing demand up to 2050.

The problem, however, could lie in execution. For instance, while announcing the National Rail Plan-2030, Prabhu also presented a White Paper on the Indian Railways in 2015. Among other things, the goal by 2020 was for the Indian Railways to increase average train speed by 50 per cent. This has been one of the biggest challenges for the Railways with average speed of freight trains plateauing at 24 kilometres per hour (kmph), which is nil improvement from 2015.

The Covid-19 months did see average freight train speeds doubling to 45 kmph in December 2020. But this could be attributed to the fact that fewer passenger trains were operating, and that the speed would revert to the lower average once normalcy returns.

Earlier this month, the Railways said freight trains have clocked a top speed of 90 kmph on the newly inaugurated Khurja-New Bhaupur section of Eastern



FAST TRACKING THE BUSINESS PLAN: SOME POSSIBLE SCENARIOS

Parameter	Current	Scenario 1	Scenario 2	Scenario 3	Scenario 4
Operating speed (kmph)	25	25	50	50	25
Railway tariff	Business as usual	Business as usual	Business as usual	30% less than business as usual	30% less than business as usual
Rail commodity share (%)	28%	24%	40%	45%	31%

Dedicated Freight Corridor. This was a first and gives a glimpse of the potential that can be tapped.

According to the latest estimates, a freight speed of 50 kmph could be coupled with 30 per cent reduction in transport costs from a business-as-usual scenario on the railway network. These faster trains will help the Railways get more share of the total freight ecosystem, with estimates pitching the modal share to 44 per cent (see table). If the speed is not upped, faster trucks on the road would lead to Railways losing out share, dropping further from the 27 per cent it currently ferries.

The vision documents do not offer much help with the actual execution of long-term projects. At best, they offer some perspective of successive governments' ambitions

The expansion of freight corridors would lower the pressure on the railway tracks by allowing speeding freight and passenger trains. The eastern freight corridor (1,875 route km) is to connect Ludhiana to Dankuni (near Kolkata) via Dadri and the western corridor (1,506 route km) will connect Navi Mumbai to Dadri near Delhi. These corridors are also planned from North to South and to Mumbai. About 350 km each have been inaugurated by Prime Minister Narendra Modi recently on the western and eastern corridors.

But neither the freight corridors nor speedier trains are new concepts. Back in 2009, the Indian Railways' Vision 2020 document presented in Parliament by

then railway minister (now West Bengal chief minister) Mamata Banerjee aimed at massive addition to its route network, segregation of passenger and freight services into separate double-line corridors, and raising the speeds of passenger trains. Vision 2020 had also envisaged the implementation of at least four high-speed rail projects to provide bullet train services at 250-350 kmph.

This continuation of central themes and projects across railway visions had been recognised by Modi, too. But his stand has been that the National Democratic Alliance (NDA) government has more efficiently executed these long-awaited projects.

Inaugurating the eastern corridor, Modi said, "The [freight corridor] project was approved in 2006. Such was the situation that not even one kilometre track could be laid till 2014. After the formation of the government in 2014, officials were asked to start fresh and the budget increased by about 11 times, ₹45,000 crore. About 1,100 km of work will be completed in the next few months. Imagine, not a single kilometre in eight years, and 1100 kilometres in 6-7 years."

Modi has also been hard-selling the bullet train project, something that can be said to be already delayed going by Banerjee's Vision 2020.

Simply put, these vision documents do not offer much help with the actual execution of these long-term projects. At best, they offer some perspective of successive governments' ambitions.

CERC to embrace AI, machine learning to improve functioning

First quasi-judicial body to strengthen its digital back-end

SHREYA JAI
New Delhi, 14 January

The apex power sector regulator, the Central Electricity Regulatory Commission (CERC), is planning to set up an artificial intelligence (AI)-based regulatory expert system tool (REST) for improving access to information and assist the commission in discharge of its duties.

So far, only the Supreme Court (SC) has an electronic filing (e-filing) system and is in the process of building an AI-based back-end service.

The CERC will be the first such quasi-judicial regulatory body to embrace AI and machine learning (ML). The decision comes at a time when the CERC has been shut for four months, following an SC order.

According to the data available on the CERC website, there are 1,000 cases pending with the regulator while it was shut. In 173 cases, the order has been reserved by the CERC, but not pronounced yet. There are 450 fresh applications pending for hearing.

The CERC floated a request for proposal (RFP) in December to select a consultant working in the domain of AI, ML natural language processing to develop AI-based REST for the CERC.

The commission in the RFP said REST was for the purpose of "building institutional memory and for cre-



TAKING THE DIGI ROUTE

- To use AI-based search tools and input-data analysis
- Automatic legal document creation & assembly
- Process automation & data visualisation tool
- Data visualisation tool to have dashboards for data trends, data analytics of

- regulatory compliance and petition status, etc.
- Single data repository/institutional memory for all the data
- Intuitive user interface
- Scalable to additional third-party software/ data sources/ tool integrations in future

ation, reference, and intelligent retrieval of information/documents to assist the commission in discharge of its functions under the Electricity Act, 2003". The CERC has a management information system (MIS) called System for Adjudication Using Digital Access & Management of Information (SAUDAMINI)

for sourcing data. However, officials said an intelligent system was needed to handle the increasing workload and widening the gamut of cases.

In the RFP issued by the CERC, it said over the years, the number of petitions filed before the CERC had increased manifold and the orders issued by the commission have ranged over an

increasing number of topics/issues.

"Therefore, the monitoring and analysing of such orders have become a challenging task for the CERC. In addition, the CERC regularly receives information from the regulated entities/stakeholders/nodal bodies. The information received is important from a regulatory perspective. However, such information generally contains voluminous inter-related data of a complex nature," said the RFP.

The agency hired for setting up REST for the CERC will need to provide AI-based search and recommendation, an automated system creation and extraction of legal documents, and develop process automation data visualisation tools. The new system will be later merged with the existing MIS SAUDAMINI, said the CERC.

While the commission is yet to receive bids, the deadline for developing the new back-end system is six months from the date of selection of the consultant.

Recently, following the Covid-induced lockdown, the SC moved to e-filing of legal documents and had initiated online hearing as well.

Similar guidelines for high courts and district courts have been issued. Once all courts are plugged into a central system, AI-based portals will enable efficiency and reduce paperwork.

DECODED

Trump impeached, again: Here's what happens next

DHRUV MUNIAL
New Delhi, 14 January

The US House of Representatives on Wednesday voted 232-197 to impeach President Donald Trump for his alleged role in inciting rioters who stormed the Capitol building on January 6. This is the second time Trump has been impeached, a first in the history of American politics. Here is a breakdown of this latest development and its varied implications.

What are the charges against Trump?

On Monday, House Democrats filed a single article of impeachment — "incitement of insurrection" — against Trump. On January 6, hours before his supporters laid siege to the Capitol, where the Congress was conducting a joint session to certify the election outcome, Trump had addressed some of them, claiming election fraud and urging them to "fight like hell". He even promised to accompany them, but eventually opted not to. The rampage in Washington left at least five people, including a police officer, dead.

What happens next?

Impeachment proceedings against a sitting president constitute political wrongdoing — it is not a criminal process. The House of Representatives is only the first step in this process. Impeachment proceedings may be initiated by any House member, with the speaker then deciding whether it has the merit to be taken forward.

On this occasion, 210 Democrats introduced the latest article of impeachment. Ten Republicans, members of Trump's own party, also voted against



him, stating that he is a threat to "national security, democracy and the constitution if allowed to remain in office..." The members also mentioned the constitution's 14th Amendment, stating that it "prohibits any person who has engaged in insurrection or rebellion against the United States" from holding office.

Now the matter will be taken up by the Senate, where Trump will face a trial. The trial will be presided over by the US chief justice and will require a two-third majority for Trump to be deemed officially impeached. If that doesn't happen, then a president is considered impeached but is not removed.

Does it make sense to impeach Trump, given that he has already been voted out of office?

The Senate is likely to commence after recess on January 19, which means that Trump's fate will most probably not be known until after he leaves the White House on January 20. For now, he can continue in his position. However, if convicted by the Senate, the move can have long-term ramifications on Trump's political career: He may be banned from holding any federal office in the future, among other punish-

ments, such as losing out on Secret Service cover, a fat retirement pension and related benefits. The latter is one of the key reasons why the House pursued his impeachment so aggressively.

Why was he impeached the first time?

In December 2019, the House had moved to impeach Trump for his alleged involvement in illegally coercing Ukraine and other countries into providing damaging narratives about then Democratic presidential primary candidate, Joe Biden, as well as promoting a dubious conspiracy theory that it was Ukraine, and not Russia, that had interfered in the 2016 presidential election.

The House cited two articles of impeachment against Trump: "Abuse of power" and "obstruction of Congress". He was bailed out by the Senate, with neither count able to command a majority.

Which other US presidents have been impeached?

Trump is the first president to be impeached twice: Andrew Johnson in 1868 and Bill Clinton in 1998. Johnson faced impeachment after tussling with a Republican-dominated House over "the rights of those who had been freed from slavery". Clinton had to endure a similar ordeal for the apparent cover-up related to his affair with White House intern Monica Lewinsky. Both were saved by the Senate, and completed their respective terms in office.

In 1974, Richard Nixon was slapped with three articles of impeachment in connection to his involvement in the Watergate scandal. But he ended up resigning before the House could proceed to impeach him.

Dixon
DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LIMITED
Registered Office: B-14 & 15, Phase-II, Noida, Gautam Buddha Nagar, UP-201305
E-Mail: investorrelations@dixoninfo.com
Website: www.dixoninfo.com
Phone: +91-120-4737200
Fax: 0120-4737263
CIN: L32101UP1993PLC066581

NOTICE
Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 2nd February, 2021, to inter-alia, consider and approve the Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results (provisional) for the Quarter ended as on 31st December, 2020.

Further, in accordance to the Reg. 46 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the details of the aforesaid meeting are available on the website of the Company i.e. www.dixoninfo.com and the website of the Stock Exchanges where the Company's shares are listed viz. BSE Limited (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

For Dixon Technologies (India) Limited
Sd/-
Ashish Kumar
Place: Noida Group Company Secretary,
Date: 14.01.2021 Head - Legal & HR

कोच्चिन पोर्ट ट्रस्ट
COCHIN PORT TRUST
Finance Department, Willingdon Island, Cochin - 682 009.
फोन/Phone: 0484-2582639 • फैक्स/Fax: 0484-266582
• ईमेल/Email: fa@cochinport.gov.in

संख्या No. FD/Costing/SEIS/18-19/2020 दिनांक Dated 00/00/2021

E-AUCTION NOTICE

- E-auction in two cover system are invited by the FA&CAO, Cochin Port Trust, Willingdon Island, Cochin 682009 for the "SALE OF DUTY CREDIT SCRIP FOR THE YEAR 2018-2019 ISSUED BY DIRECTOR GENERAL OF FOREIGN TRADE (DGFT) UNDER SERVICE EXPORT FROM INDIA SCHEME (SEIS) FOR VALUE OF ₹ 7,90,37,573.00".
- Details of e-auction can be downloaded from CoPT website www.cochinport.gov.in, www.mstcecommerce.com or Central Public Procurement Portal www.eprocure.gov.in/cppp/ from 15.01.2021 to 08.02.2021 1700 HRS.
- All intending bidders for participating in E-Auction will have to register with MSTC in their portal www.mstcecommerce.com, by paying applicable registration fees. User ID & password for log-in to e-Tendering portal www.mstcecommerce.com will be issued by MSTC on completion of registration process. Bidders registered with MSTC can participate in the e-auction.
- Earnest Money Deposit (EMD) of ₹ 7,90,376/- is to be remitted to Cochin Port Trust, through State Bank Collect / NEFT / RTGS.

Sd/-
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER COCHIN PORT TRUST

Business Standard
DELHI EDITION

Printed and Published by Nandan Singh Rawat on behalf of Business Standard Private Limited and printed at The Indian Express (P) Ltd. A-8, Sector-7, Noida, Gautam Budh Nagar-201301 and published at Nehru House, 4 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 110002

Editor : Shyamal Majumdar

RNI NO. 57376/1994

Readers should write their feedback at feedback@bsmail.in
Ph. 011-23720202, Fax: +91-11-23720201

For Subscription and Circulation enquiries please contact:
Ms. Mansi Singh
Head-Customer Relations
Business Standard Private Limited.
H/4 & 1/3, Building H,Paragon Centre, Opp. Birla Centurion, PB.Marg, Worli, Mumbai - 400013
E-mail: subs_bs@bsmail.in "or sms, SUB BS to 57007"

DISCLAIMER News reports and feature articles in Business Standard seek to present an unbiased picture of developments in the markets, the corporate world and the government. Actual developments can turn out to be different owing to circumstances beyond Business Standard's control and knowledge. Business Standard does not take any responsibility for investment or business decisions taken by readers on the basis of reports and articles published in the newspaper. Readers are expected to form their own judgement.
Business Standard does not associate itself with or stand by the contents of any of the advertisements accepted in good faith and published by it. Any claim related to the advertisements should be directed to the advertisers concerned.
Unless explicitly stated otherwise, all rights reserved by M/s Business Standard Pvt. Ltd. Any printing, publication, reproduction, transmission or redissemination of the contents, in any form or by any means, is prohibited without the prior written consent of M/s Business Standard Pvt. Ltd. Any such prohibited and unauthorised act by any person/legal entity shall invite civil and criminal liabilities.

No Air Surcharge

FORM B
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016)
FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF KWALITY LIMITED

1 Name of corporate debtor	Kwality Limited
2 Date of incorporation of corporate debtor	21-08-1992
3 Authority under which corporate debtor is incorporated / Registered	Registrar of Companies - Delhi
4 Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	L74899DL1992PLC255519
5 Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Registered & Principal Office: KDIL House, F-82, Shivaji Place, Rajouri Garden, New Delhi West, Delhi - 110027, India.
6 Date of closure of Insolvency Resolution Process	11-01-2021
7 Liquidation commencement date of corporate debtor	11-01-2021
8 Name and registration number of the Insolvency professional acting as liquidator	Mr. Shailendra Ajmera Reg. No: IBBI/IPA-001/IP-P00304/2017-18/10568
9 Address and e-mail of the liquidator, as registered with the Board	Ernst & Young LLP, 3rd Floor, Worldmark 1, Aerocity Hospitality, New Delhi, National Capital Territory of Delhi - 110037 Email: Shailendra.ajmera@in.ey.com
10 Address and e-mail to be used for correspondence with the Liquidator	Mr. Shailendra Ajmera, Liquidator of Kwality Limited Ernst & Young LLP, 3rd Floor, Worldmark 1, Aerocity Hospitality, New Delhi, National Capital Territory of Delhi - 110037 Email for submission of Claims: liquidator.kwalityclaims@in.ey.com Email for all other correspondence (except for submission of claims): liquidator.kwality@in.ey.com Email registered with IBBI: Shailendra.ajmera@in.ey.com
11 Last date for submission of claims	09-02-2021

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, New Delhi has ordered the commencement of liquidation of the **Kwality Limited** on 11.01.2021. The stakeholders of **Kwality Limited** are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 09.02.2021 i.e. thirty (30) days from the liquidation commencement date, to the Liquidator at the address mentioned against item No.10 mentioned above. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with the proof in person, by post or by electronic means.
Submission of false or misleading proof of claims shall attract penalties
Date : 15-01-2021 Name and signature of liquidator:
Place: New Delhi Mr. Shailendra Ajmera